

अध्यक्ष महोदय : अब स्वामी जी, अगर मैं उठाने की इजाजत न दूँ तो आप नाराज हो जायेंगे वैसे व्यवस्था में इस में क्या दूँ ?

श्री रामेश्वर नन्द : इसी से सम्बन्धित है, इस में उठ जाता है और इस में लिखा भी हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, आप अपने आप को ही समझाइये कि ऐसा सवाल व्यवस्था का नहीं उठाया जा सकता है ।

Shri Narendra Singh Mahida: There are many Government agencies through which these seeds are distributed. Is the Government aware that many of the seeds distributed do not bloom even?

Shri Shahnawaz Khan: Some complaints have been received. We have drawn the attention of the State Governments who are responsible for supervising these farms, to look into those complaints.

Shri Kapur Singh: In this morning's papers, we have read about extensive appearance of black-wheat crops in U.P. We would like to know from which Government Seed Farm this seed originated?

Shri Shahnawaz Khan: We will be collecting that information.

Shri C. Subramaniam: The hon. Member may be interested to know that this seed came from Punjab.

Mr. Speaker: Probably, he would like to know the district and the village also.

Shri Biahwanath Roy: In view of the different climatic conditions in the different districts in the States, may I know whether the Government have got any proposal under consideration for starting big farms at district level?

Shri Shahnawaz Khan: We intend to start a large number of these farms depending on the availability of land. In the beginning, we hope to start a farm in each State and we hope that

it will further be extended to districts.

पंचायतों की वित्तीय स्थिति

+

* 646. { श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद .
श्री कोस्ता बैकिया :
श्री राम हरस यादव :
श्री दे० जी० नायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायतों के वित्तीय श्रोतों का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गयी बलवन्तराय मेहता समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy): (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the main recommendations contained in the interim report is laid on the Table of the House. [Placed in Library, See No. LT-4091/65].

(c) The Interim Report of the Committee has been considered by the Consultative Council at its meeting on the 29th March, 1965, and is now under the consideration of the Government.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पंचायतों के पास पंचायती राज लाने के लिए पैसे का बड़ा अभाव है और उस में यह सिफारिश की गई है कि केन्द्रीय सरकार को कुछ अनुदान

देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए । तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार किस निश्चय पर पहुँची है ?

Shri B. S. Murthy: In the statement laid on the Table of the House, it has been stated that there must be a provision made by the Central Government that. . .

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह सवाल का जबाब नहीं हो रहा है ।

Shri B. S. Murthy: May I request the hon. Member to repeat the question?

Mr. Speaker: He ought to have asked for it in the beginning.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मेरा यह सवाल था कि इस रिपोर्ट में यह साफ़ कहा गया है कि पंचायती राज कों चलाने के लिए पंचायतों में पैसा "नहीं" है इसलिए केन्द्रीय सरकार को पंचायतों को अनुदान देना चाहिए तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस अनुदान को देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या फैसला किया है ?

Shri B. S. Murthy: The Report has just come and the Ministry concerned is considering it. It has to move other departments concerned in the States. Therefore, we cannot at present say as to what decision the Centre is going to take.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस रिपोर्ट में और सिफारिशों के साथ एक सिफारिश यह भी है कि पंचायतों को और अधिक कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या फैसला किया है, राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में क्या सलाह दी है । और पंचायतों को इस सम्बन्ध में क्या राय दे है ?

Shri B. S. Murthy: The panchayats have already been authorised to levy

certain taxes, under the respective State legislative enactments. And those taxes could be classified as follows: (a) proceeds from taxes levied by them; (b) fees and charges imposed; (c) income from property, investments and remunerative undertakings; and generally, the panchayats can levy taxes on houses, vehicles and profession.

As a result of these taxes, I may say that in the Maharashtra State, in the year 1962-63, the panchayats had got non-grant income to the extent of Rs. 474.50 lakhs, whereas the minimum figure was in Bihar, and it was Rs. 0.45 lakhs.

श्री यशपाल सिंह : इस स्टेटमेंट में श्रीर सब कुछ लिखा गया है और मेहता कमेटी की रिपोर्ट में भी सब कुछ लिखा गया है अलबत्ता एक बात नहीं लिखी गई है कि पंचायतों को जो पंचायत कर वसूल करना पड़ता है उस का अभी लाखों रुपये बाकी पड़ा है और लाखों रुपये का गबन हो चुका है तो जब यह लोग रेव्यू वसूल करेंगे, राजस्व वसूल करेंगे उस वक्त यह किस तरीके से इंतजाम कर सकेंगे और इतनी बड़ी धनराशि को कैसे इक्ट्ठा कर सकेंगे और अगर इस राजस्व को ले कर पंचायतों को दे दिया जाय तो इससे देहातों का क्या फायदा होगा ?

Shri B. S. Murthy: I do not think that the hon. Member is speaking with full knowledge of the situation.

श्री यशपाल सिंह : यह आपका खुद का स्टेटमेंट है किसी और का नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इस में तो वह बात है नहीं ।

Shri B. S. Murthy: I would beg to state that the statement does not contain anything which the hon. Member has stated now.

In Andhra Pradesh, the Government have entrusted the collection of land revenue with the panchayats, and the

report is that cent per cent collection was made, as a result of which the panchayats are getting about Rs. 4000 to Rs. 8000 as commission. But, generally, the collection is entrusted not to the village panchayats they are to levy it, but the collection is entrusted to the revenue authorities. Therefore, there is no difficulty as far as the panchayats levying the tax is concerned.

श्री यशपाल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना बाकी पड़ा हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : एक सवाल खड़े होकर और एक सवाल बैठ कर ।

श्री राम हरल्ल यादव : पंचायतें प्रजातंत्र की बुनियाद हैं, उनके ऊपर हमारे देश का सारा ढांचा निर्भर है तो इस वक्त जो शोचनीय हालत है उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट क्या क्रदम उठा रही है, खास कर उत्तर प्रदेश में जहां कि यह बहुत असें से कायम है ?

Shri B. S. Murthy : I have already stated that here is a statement which has been laid on the Table of the House, which contains certain proposals. Either the Central Government can give grants direct or the President can give a direction to the Finance Commission to look into the matter and see whether the grants given to the State Governments can be allotted according to the needs of the panchayati raj. These things have to be processed and it requires a lot of time.

श्री बिदवानाथ पाण्डेय : जैसा कि मालूम होता है धन के अभाव में पंचायतों राज अपने काम को सुन्दर तरीके से नहीं कर पा रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्हें सुन्दर तरीके से चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है और उस धन की व्यवस्था के लिए सरकार क्या करना चाहती है ?

Shri B. S. Murthy : To be fair to the State Governments, we must agree that the State Governments are doing

their best. They are also giving grants and the power to levy taxes. But all this is not enough. Therefore, this committee has recommended that much more money has to be given, and these things have to be processed.

Shri Shree Narayan Das : In view of the fact that a study team was appointed by this Ministry to go into the financial resource of panchayat Raj Institutions, I would like to know what was the necessity for this another committee and what were the special terms of reference given to this committee, which is another committee appointed to study the matter?

Shri B. S. Murthy : That committee was appointed only to go into the question of panchayati raj institutions' resources. This committee has gone into various other aspects.

Shri Shree Narayan Das : What are those other aspects?

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या यह सही है कि जिन पंचायतों में गबन और षोडाला हुआ है, चूँकि वे कांग्रेसियों के हाथ में हैं, इस लिए ऐसा हुआ है ?

Shri B. S. Murthy : Congress members never enjoy any monopoly.

श्री युद्धवीर सिंह : इस विवरण में बताया गया है कि इस कमेटी ने पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं। इस संदर्भ में आन्ध्र का भी जिक्र किया गया है कि वहां पर मालगुजारी (लैंड रेवेन्यू) की उगाही का काम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया गया है और वह काम अच्छे तरीके से चल रहा है। देश के शेष भागों का तजुर्बा यह है कि पंचायतों ने अपने गांवों में मालगुजारी के अतिरिक्त जो टेक्स लगा रखे हैं, उन का पचास प्रतिशत भी इकट्ठा नहीं हो पाता है। क्या सरकार कोई ऐसा सुझाव या मेशीनरी या साधन राज्य सरकारों को बताने की

स्थिति में है, जिस से पंचायतों के टेक्सों की उगाही सुचारु रूप से हो सके ?

Shri B. S. Murthy: As far as land revenue is concerned, Andhra Pradesh is giving 25 P., Assam is giving 15 P. and Bihar 6½ P. The view of the State Governments is to gradually give all the land revenue to the panchayats.

श्री युद्धवीर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि लैंड रेवेन्यू के अलावा और जो टेक्स पंचायतों लगाती हैं, सरकार उन की उगाही के बारे में क्या कर रही है।

Shri B. S. Murthy: All the expenditure which the State Government incurs on education, road building, health and other subjects, all these monies are also transferred to the panchayati raj bodies.

Mr. Speaker: The panchayats in States other than Andhra are not able to realise the amounts due to them. What is being done....

Shri Yudhvir Singh: Other than land revenue.

Mr. Speaker: What is being done to help them recover it?

Shri B. S. Murthy: All the State Governments are transferring large sums of grants to undertake certain agency functions.

श्री युद्धवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह क्या स्थिति है कि आप के इतनी दफ्ता कहने के बावजूद भी मेरे प्रश्न का ठीक जवाब नहीं दिया जा रहा है

The Minister of Community Development and Co-operation (Shri S. K. Dey): State Governments are trying their utmost to help the panchayats secure the tax resources which they levy on the people. The present thinking is that we should ask the State Governments to let the revenue agency collect all the taxes

of the panchayati raj institutions. We have yet to take a final decision in the matter.

Shri S. M. Banerjee: I would like to know whether it is a fact that in these panchayat administrations, the major portion of the financial aid given to them is utilised by the ruling party for the purposes of elections and to prepare the ground for the elections (*laughter*)?—Do not laugh, it is true.—What is the check on this? Is there any machinery to check such extra or wasteful expenditure on these elections?

Shri S. K. Dey: The information supplied by the hon. Member is, to the best of my knowledge completely without any foundation.

Shri Daji: Is the Government aware that in order to avoid the commitment of giving more financial resources to panchayats, many states like Madhya Pradesh are avoiding the inauguration of panchayati raj from year to year? It is now more than two years, and despite the promise that it would be done, panchayati raj has not been ushered in Madhya Pradesh. What does Government propose to do about it?

Shri S. K. Dey: I am happy to say that this is not correct. I have received the assurance of the Chief Minister of Madhya Pradesh that before the onset of this monsoon, panchayati raj will be in operation in the State.

Shri Kapur Singh: He is happy, but has he ascertained the facts for himself?

Mr. Speaker: He got the information from the Chief Minister.

श्री शिव नारायण : सन्तानम् कमेटी बँठी हुई थी। उस के बाद एक नई कमेटी बिठाई गई। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कमेटी किन किन विषयों की जांच करने के लिए बिठाई गई और क्या उस ने यह रिपोर्ट भी दी है कि पंचायत-राज को तोड़ दिया जाय।

Shri S. K. Dey: There is no question of disbanding the Panchayat institutions. Nobody can disband the institutions now. The subjects that were entrusted to the Balwant Rai Mehta Committee for study were entirely different from the subjects that were remitted to the Santhanam Committee on financial resources. What was remitted to the Balwantrai Mehta Committee has already been listed in the papers that have been laid on the Table of the House.

Mr. Speaker: I do not think any further supplementaries after this answer are required.

Air-India Advertisement

- +
647. { **Shri P. C. Borooah:**
Shri Yashpal Singh:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri P. G. Sen:
Shri Ram Sewak:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of Civil Aviation be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kashmir was eliminated from the map of India being used by the Air-India in an advertisement published in the 'New York Times' which appeared in January, 1965;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken against the persons responsible for this?

The Minister of Civil Aviation (Shri Nityanand Kanungo): (a) to (c). I lay a statement on the Table of the House.

Statement

(a) and (b). The advertisement captioned "We should say once that Air-India jets to Bombay daily and has the fastest service to New Delhi" was prepared by the Air-India's advertising agents in New York to highlight the Corporation's jet services to Bombay and Delhi. Bombay and Delhi were pin-pointed in a 'rough'

outline of India and not a geographical map. There was no intention to show the political or geographical boundaries of India. Since the advertisement was liable to be misunderstood, it was withdrawn immediately by the Corporation.

(c) All concerned in Air-India have been suitably instructed to be very careful whenever using maps depicting boundaries of India.

Shri P. C. Borooah: May I know under what circumstances this self-damaging and misleading map was published by a Government advertising agency, how much time after the publication of this map this defect was noticed, and what steps have been taken to correct it?

Shri Kanungo: As has been said in the statement, it was not a map of India, because large portions of India are not shown in it. However when a PTI message from New York showed that there was some misunderstanding, it was immediately withdrawn, and the revised advertisement went into circulation.

Shri P. C. Borooah: In view of the fact that even the Government agencies pay scant regard for the sanctity of the map of India, may I know whether Government proposes to restrict or regulate the publication of maps for advertisement purposes; if so, what steps have been taken in that regard?

Shri Kanungo: As already stated, this is not a map of India. It was only a portion of India highlighting two points, Bombay and Delhi, for the jet services.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि यह हिन्दुस्तान का रफ़ मैप था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस में काश्मीर के अतिरिक्त हिन्दुस्तान के कौन से हिस्से नहीं दिखाए गये थे और यदि केवल काश्मीर ही नहीं दिखाया गया था, तो क्या उस से यह स्पष्ट